

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन: विभिन्न पक्षों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

श्रीमती हेमलता¹

¹असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, दयानन्द गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज, कानपुर उ0प्र0

Received: 20 March 2026 Accepted & Reviewed: 25 March 2026, Published: 31 March 2026

Abstract

प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सामग्रियां हैं जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं और जो हमारे जीवन चक्र को सुचारु रूप से चलाने हेतु उपयोगी हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत हवा, पानी, मिट्टी, जीवाश्म ईंधन, खनिज, वन, वनस्पति एवं जीव-जन्तु सभी सम्मिलित हैं। इन सभी का उपयोग हम भोजन, वस्त्र, औषधियों, आश्रय एवं विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों की प्राप्ति हेतु करते हैं। मानवीय हस्तक्षेप के कारण इनके प्राकृतिक स्वरूप में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं जिसका कुप्रभाव मानव जाति एवं संपूर्ण जैव विविधता पर पड़ रहा है। भारतीय दर्शन सदैव से ही प्रकृति संरक्षण का संदेश प्रेषित करता रहा है, यही कारण है कि प्राचीन काल से वर्तमान तक हम सभी भावनात्मक रूप से प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हमारी पुरातन संस्कृति प्रकृति को पूजनीय मानती आयी है जैसे कि सदानीरा नदियां हों अथवा हमारी धरित्री जो कि माँ स्वरूपा श्रद्धेय मानी गयी है। इसी क्रम में भारतीय संस्कृति में विभिन्न वृक्षों एवं सूर्य एवं चन्द्रमा को भी ईश्वर स्वरूप मानकर पूजा अर्चना की जाती है। कह सकते हैं कि सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक क्रिया-कलापों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भी प्रकृति है तो मानव जाति का अस्तित्व है अन्यथा हम शून्य हैं।

प्रकृति को संरक्षित करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि जीवन को बचाने हेतु एक अति आवश्यक कदम है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए भारत सहित वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। हमारे देश की भौगोलिक दशायें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अनुकूल हैं, जिनके सतत उपयोग के द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण के दुष्परिणामों का स्तर कम किया जा सकता है। जैव विविधता के संरक्षण एवं अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने एवं इससे सम्बन्धित नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुख्य नोडल एजेंसी के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC- Ministry of Environment, Forest and Climate Change) का गठन किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकृति के संरक्षण हेतु नवीन नियमों व कानूनों को निर्मित किया गया है जिनमें समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं।

मुख्य शब्द— पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, भारतीय जैव विविधता, दर्शन, नवीकरणीय संसाधन, मानव जाति।

Introduction

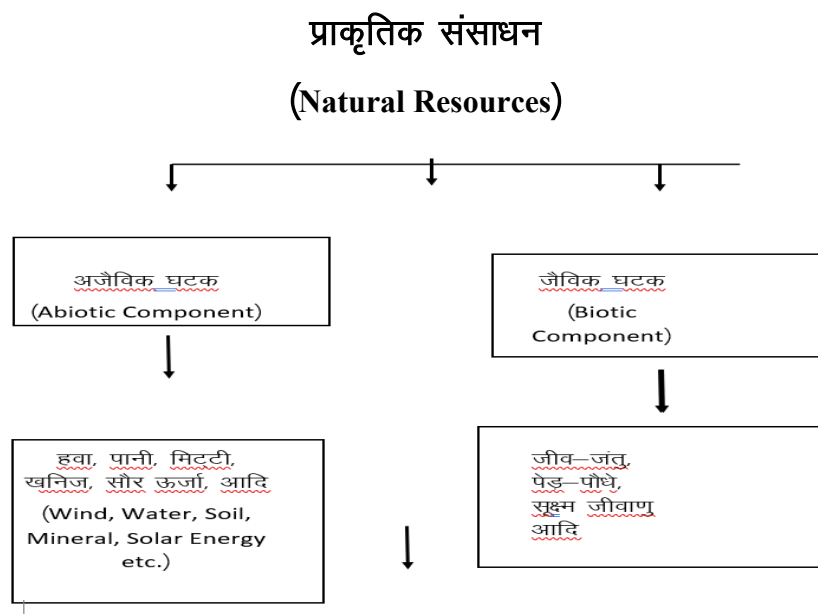
‘पर्यावरण’ वह है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। यह जैविक एवं अजैविक रूप से जीवनपर्यन्त हवा, मिट्टी, पानी, वृक्ष, खनिज इत्यादि सेवायें प्रदान करता है। प्रकृति के अजैव घटकों एवं विशिष्ट सजीव जीवों के आपसी अभिक्रिया के कारण ही विभिन्न प्रकार के परितंत्रों (Ecosystems) का निर्माण होता है। मोटे तौर पर हम प्रकृति को दो भागों में बांट सकते हैं—

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

प्राकृतिक संसाधन : एक परिचय— भारत सहित विश्व की अन्य सभ्यताओं का विकास हमेशा जीवनदायिनी नदियों के तट पर होता रहा है। सभ्यता निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहा है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को जीवनदायिनी माना गया है एवं इसके संरक्षण की परम्परा प्राचीनकाल से ही चली आ रही है क्योंकि प्रकृति और मानव जाति एक दूसरे के पूरक हैं। भारत देश परम्पराओं एवं त्योहारों का देश है जिसका उत्सव प्रकृति की गोद में सम्पन्न होता है। पोंगल, छठ, हरियाली तीज जैसे त्योहार, प्रकृति के महत्व को दर्शाते हैं। इन सभी तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमें अपनी वसुंधरा की धरोहर की रक्षा करनी ही होगी क्योंकि प्रकृति हमारी “माँ” जैसी है। हमारे देश के मूल निवासी अर्थात् आदिवासी समुदाय प्रारम्भिक अवस्था से वर्तमान तक, प्रकृति की छत्र-छाया में ही जीवनयापन करते आए हैं।



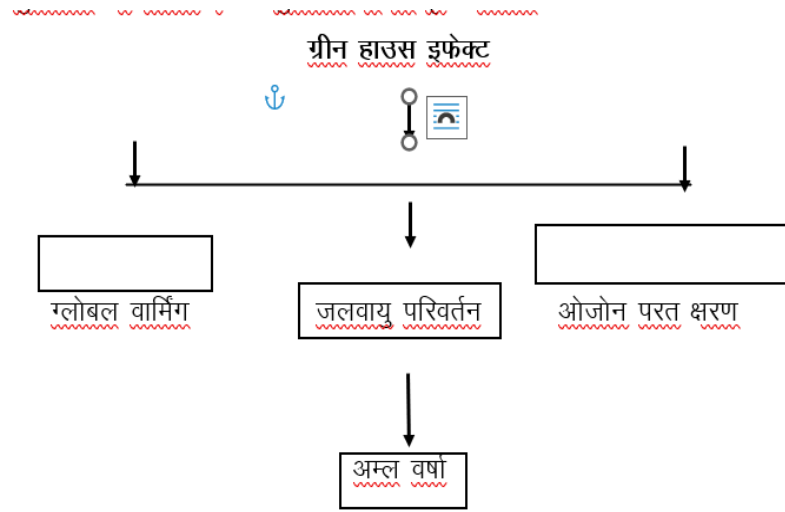
विकास की प्रारम्भिक अवस्था में घास के मैदान एवं जंगलों, झीलों एवं नदियों पर ही सम्पूर्ण मनुष्य जाति पूर्णतः निर्भर थी। धीरे-धीरे फसलें उगाने एवं पालतू पशुओं के उपयोग की क्षमता बढ़ने पर पारितंत्रों के स्वरूप में परिवर्तन होता गया एवं यह पारितंत्र खेतिहर जमीनों में बदलते गये। आगे चलकर परम्परागत कृषकों द्वारा भूमिगत जल के उपयोग हेतु 'कुओं' का निर्माण किया एवं जलप्रवाह को रोकने हेतु बांधों को भी विकसित किया गया। नित नवीन आविष्कारों एवं बढ़ती तकनीकों द्वारा मानव जीवन आसान होता गया जिससे सीधे तौर पर जनसंख्या वृद्धि होती गयी। आज भारत, सम्पूर्ण विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है, अतः बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति का लक्ष्य 'हरित क्रान्ति' के द्वारा एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों से पूर्ण करने का प्रयास किया गया। परिणामस्वरूप जहाँ एक तरफ भारत देश में गेहूँ की पैदावार में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया वहीं अन्य पैदावार की स्थिति भी अत्यधिक सुधार हुआ। किन्तु भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए रसायनों एवं उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में उपजाऊ भूमि बंजर हो गयी। वर्तमान में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रसायनों के प्रयोग एवं वनोन्मूलन के कारण विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के परिणाम

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

दृष्टिगोचर हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन का ही परिणाम है कि अत्यधिक बाढ़, सूखा, शीत एवं प्राकृतिक आपदाओं से मानवजाति त्रस्त है।



भारत सहित वैश्विक स्तर पर जैव-विविधता को खतरा उत्पन्न हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंतर्गत पर्यावरण हेतु वैश्विक स्तर पर कार्य करने वाले संगठन (UNEP) द्वारा वन्यजीवों की संख्या से सम्बन्धित लाल, हरी एवं गुलाबी सूची को जारी किया जाता है। प्रकृति के तीव्र दोहन का ही परिणाम 'जलवायु परिवर्तन' के रूप में हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। आज प्रकृति का विकराल होता रूप मानवीय क्रियाकलापों का ही परिणाम है जिसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अम्ल वर्षा एवं ओजोन परत क्षरण जैसे प्राकृतिक घटनायें आज संपूर्ण विश्व को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन बिगड़े हुए मौसम चक्र का ही परिणाम है। इसी कारण वैश्विक स्तर पर वर्षा का पैटर्न बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की एकाग्रता बढ़ रही है जिससे वातावरण गर्म हो रहा है और कृषि उत्पादकता भी प्रभावित हो रही है। बादल फटना, भूकम्प आना, लैण्ड स्लाइडिंग लगातार जारी है। मौसम के निरन्तर परिवर्तन के कारण रोगों और कीटों का भौगोलिक पुनर्वितरण हो रहा है। आज हमें निर्वहनीय जीवन शैली की आवश्यकता है, जिससे आवश्यक रूप से मानव जीवन की गुणवत्ता एवं पारितंत्रों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी।

अध्ययन पद्धति (Methodology) :- प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धतियों के साथ ही विभिन्न सामाजिक एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया है। डेटा संग्रहण के लिए विभिन्न माध्यमों के द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। शोध पत्र के विषय पर मानवीय दृष्टिकोणों में गहराई से अन्तर्दृष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से गुणात्मक डेटा विश्लेषण को भी सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत लेख प्रकृति संरक्षण से सम्बन्धित होने के कारण पारिस्थितिकीय (Ecological) एवं सामाजिक पद्धतियों (Sociological Method) के संयोजन का उपयोग करता है।

उद्देश्य (Objectives) :- यह शोध पत्र अध्ययन के निम्न विषयों पर चिंतन एवं विश्लेषण करता है—

- प्राकृतिक पारिस्थितिकी, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा सुनिश्चित करना।

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

- प्रकृति के सतत उपयोग हेतु मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के उपायों पर चिन्तन करना।
- प्राकृतिक संसाधनों के अपव्ययी उपयोग को रोकना ताकि प्रकृति सुरक्षित रहे एवं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो।
- प्राकृतिक विरासत की रक्षा हेतु शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रमों का सरलतापूर्वक क्रियान्वयन करना और सामुदायिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना।
- नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना ताकि प्राकृतिक संसाधन भावी पीढ़ियों द्वारा भी उपयोगी रहें।
- टिकाऊ कृषि एवं स्थायी प्रथाओं को लागू करना।
- आर्द्रभूमियों का वनों के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी करने के उपायों पर विश्लेषण।
- वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान के प्रसार द्वारा जनसमुदाय में पारिस्थितिकी संरक्षण हेतु नवीन दृष्टिकोण का सृजन करने पर विचार विमर्श करना।
- अनुसंधान द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के माध्यम से नीति निर्माण में सहायक होना एवं पर्यावरणीय समस्याओं के हल हेतु सुझाव देना।

विषय-वस्तु - प्राकृतिक संसाधनों के अति उपयोग के कारण हमारे पारितंत्र (Ecosystem) की क्षमता प्रभावित हुई है। ऐसा परिदृश्य विकासशील देशों में अधिक देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले लगभग सौ वर्षों के दौरान शिक्षा के प्रसार के परिणामस्वरूप नवीन तकनीकों एवं अनुसंधानों की उपलब्धता से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के हालातों में सुधार हुआ है। नित नवीन वैज्ञानिक स्रोतों व प्रयोगों के कारण आज मानव जाति की औसत आयु में वृद्धि हुई है साथ ही जीवन स्तर में भी तुलनात्मक स्तर से सुधार हुआ है। आधुनिक और वैज्ञानिक होते जीवन में हमने आर्थिक संवृद्धि हासिल की है एवं वृहद स्तर पर नगरीकरण व औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी एवं इस पर पाये जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है।

आज के आधुनिक एवं विकसित होते समाज में पर्वतों से लेकर नदियों एवं मैदानी इलाकों तक अनेक देशी विदेशी परियोजनाओं के स्थापन एवं क्रियान्वयन हेतु वनों का सफाया किया जा रहा है, पर्वतों को काटा जा रहा है एवं नदियों की दिशा परिवर्तन के कारण निरन्तर प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि जारी है। इन सभी क्रिया कलापों के अन्य प्रभावों में वैश्विक स्तर पर 'जैव-विविधता' आज गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। आज जीव-जन्तुओं के प्राकृतिक आवास समाप्ति की कगार पर हैं जिनको यू0एन0ओ0 (UNO) की पर्यावरण सम्बन्धी वैश्विक गतिविधियों का डेटा प्रस्तुत करने वाली संस्था (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम-UNEP) द्वारा समय-समय पर विभिन्न सूचियों द्वारा दर्शाया जाता है। पिछले कुछ दशकों में ऐसा परिदृश्य तेजी से देखा जा सकता है कि अनेक छोटे नगर बड़े नगरों में एवं बड़े नगर महानगरों में परिवर्तित हो रहे हैं जिससे इन नगरों का घनत्व भी बढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि **प्राकृतिक संसाधन सीमित** हैं अतः हमें वर्तमान उपभोग की मात्रा को सुनिश्चित करते हुए भविष्य की जरूरतों को भी सुरक्षित रखने की

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

आवश्यकता है।

प्राकृतिक संसाधन एवं मानव जीवन— औद्योगीकरण व नवीन नगरों के निर्माण हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई, जल का अत्यधिक दोहन, नवीन कलकारखानों, प्रोजेक्ट इकाइयों की स्थापना का ही नतीजा है कि वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। कार्बन डाइ ऑक्साइड, फ्रीऑन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। 'जलवायु परिवर्तन' आज वैश्विक समुदाय के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि प्रदूषण का ही परिणाम है कि आज मानवजाति गंभीर रोगों की चपेट में आ चुकी है। रसायनों के अत्यधिक प्रयोगों का ही परिणाम है कि आज कैंसर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COD), गुर्दे की गंभीर बीमारियां एवं अवसाद के अलावा एस्बेस्टोसिस मिनिमाता रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटार्ड-इटार्ड रोग, लेड पॉइजनिंग, अस्थमा जैसी अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्यायें पैदा हो रही हैं।

क्र०सं०	प्रदूषण	रोग
1.	वायु प्रदूषण	अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, मोतियाबिंद, तंत्रिका संबंधी रोग, कैंसर आदि।
2.	जल प्रदूषण	टाइफाइड, सिस्टोसोमियोसिस, जिआर्डियासिस, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस
3.	मृदा प्रदूषण	कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकार, श्वसन संबंधी रोग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी समस्यायें

विभिन्न प्रदूषणों के घातक परिणाम— जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियां या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्ति की कगार पर हैं। उदाहरणस्वरूप आज घरेलू चिड़िया गौरैया एवं अन्य पक्षियों की संख्या में तेजी से कमी आयी है क्योंकि वृक्षों की कटाई के कारण उनके प्राकृतिक आवासों की संख्या में कमी हो गयी है। इसी प्रकार प्रतिबंधित दवा (डेक्लोफैनिन) के इस्तेमाल से गिद्धों की संख्या में भी भारी गिरावट दर्ज की गयी है। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण राजस्थान के राज्यपक्षी 'गोंडावन' (ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड) का भी है जिसे यू०एन०ओ० (UNEP) की 'रेड लिस्ट' में शामिल किया गया है।

गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षियों की सूची :

Red Deta List (Birds)-

1. भारतीय गिद्ध
2. जेरडन कौरसर
3. ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड
4. ग्रेट साइबेरियन क्रेन

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

5. व्हाइट बैकड वल्चर

6. कश्मीरी स्टैग

रेड डाटा लिस्ट (जन्तु) :

Red Deta List & Animals-

1. गंगा नदी डाल्फिन

2. हलॉक गिबबन

3. नीलगिरि लंगूर

4. वन उल्लू

5. घड़ियाल

जैव विविधता को होते नुकसान के अलावा प्रकृति का प्रचण्ड रूप वैश्विक स्तर पर प्रकोप के समान हैं। साल-दर-साल भयावह होती जलवायुवीय दशायें जनमानस को डराने लगी हैं। भूस्खलन, चक्रवात, वनाग्नि, बाढ़, हीट वेव इत्यादि मौसमी घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। यदि हम पिछले वर्ष (2025) का ही ताजा उदाहरण लें तो प्राकृतिक आपदाओं ने जमकर कोहराम मचाया था। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। (प्रस्तुत आंकड़े, 26 दिसम्बर 2025, हिन्दुस्तान समाचार पत्र से लिये गये हैं)

• भूस्खलन (5 अगस्त 2025)

उत्तराखण्ड— उत्तरकाशी के धराली में पांच अगस्त को पहाड़ों के बीच से **मलबा काल बकर आया**। कुछ ही देर में पूरा इलाका मैदान बन गया। आलीशान होटल एवं कई मकानों का नामों निशान मिट गया। 52 लोग लापता थे जिनमें से पुलिस प्रशासन द्वारा 12 व्यक्तियों के शव ही प्राप्त हो सके। ऐसी तबाही देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। आज भी लोग अपनों की घर वापसी की तलाश में हैं। क्या प्रकृति का रूप इतना डरावना भी हो सकता है।

• बाढ़

जम्मू कश्मीर (14 अगस्त 2025) व हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम— मलबे में दबकर 68 लोगों की मौत हो गयी। हिमाचल में भी बादल फटने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्राकृतिक आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश को 3800 करोड़ रुपये की हानि हुई। 20 अगस्त 2025 को पंजाब के 13 जिलों के 1400 गांव जलमग्न हो गए। साढ़े तीन लाख लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ और लगभग 3.71 लाख फसल बरबाद हो गयी। कुछ यही हालात असम के थे। वहां 12,160 हेक्टेअर फसल बर्बाद हो गयी जबकि एक हजार से अधिक जानवर बहकर मारे गये।

• **हीट वेव (Heat Wave)**— भारत में प्रतिवर्ष हीटवेव से तापमान सामान्य से कई डिग्री दर्ज किया जा रहा है वहीं इटली, तुर्किये, जापान एवं अन्य यूरोपीय देशों में रेड हीट अलर्ट जारी किया गया।

• आग (Fire) वनाग्नि (Wildfire)

1. **भारत** — पूरी दुनिया सहित भारत में भी जंगल में आग की घटनायें साल प्रति साल बढ़ती जा रही हैं।

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक (97) घटनायें होती हैं। उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ में 23 और जम्मू कश्मीर में 94 एवं महाराष्ट्र में 21 घटनायें घटी। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साल 2025 जून तक भारत में वनों में आग की 2,38,309 घटनायें हुई जिससे 36 प्रतिशत वन क्षेत्र प्रभावित हुए।

2020 – 2,38,309

2024 – 2,03,544 देश के वनों में आग की घटनाओं के आंकड़े

2025 – 2,23,333

2. अमेरिका (America)— सात जनवरी 2025 को लॉस एंजिल्स के जंगल आग से धधकने लगे। जंगलों के 14 स्थानों पर लगी आग से पूरा शहर प्रभावित हुआ। 400 व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं 18 हजार घर और मूलभूत ढांचे आग में स्वाहा हो गए। दो लाख लोगों को कैंप में आसरा दिया गया।

3. ब्रिटेन (Britain)— वर्ष 2025 में लगी आग के कारण 47,879 हेक्टेअर वन क्षेत्र जलकर राख हो गया। वर्ष 2019 में लगभग 47 हजार हेक्टेअर जंगल जले थे। यूरोपियन फारेस्ट फायर इन्फारमेशन सिस्टम के अनुसार 28 जून को स्कॉटलैण्ड के दावा क्षेत्र के वनों में आग से 12 हजार हेक्टेअर में फैला जंगल जलकर राख हो गया।

● चक्रवात (Cyclines)

मोंथा (Montha)— अक्टूबर में देश में चक्रवाती तूफान 'मोंथा' से चार चटीय राज्य (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु) प्रभावित हुए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड व छत्तीसगढ़ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। कुछ व्यक्तियों की मृत्यु के साथ ही 76 करोड़ डालर की संपत्ति का नुकसान हुआ।

● **सेन्यार (Senyar)**— नवम्बर 2025 में आए चक्रवात 'सेन्यार' का असर थाइलैण्ड, इण्डोनेशिया एवं सुमात्रा पर हुआ। थाइलैण्ड में सर्वाधिक 297 मौतें हुई एवं करीब 1300 व्यक्तियों को जान गंवानी पड़ी।

● भूकम्प (Earthquake)

➤ तिब्बत के टिंगरी काउंटी में सात जनवरी को 7.1 तीव्रता का भूकम्प आया जिससे 400 लोगों की मृत्यु हुई।

➤ म्यांमार—थाइलैण्ड में 28 मार्च 2025 को 80 सेकेण्ड तक 7.9 तीव्रता का भूकम्प आया जिससे 5456 मौतें हुई।

➤ दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली भूकम्प 2011 में रूस के कमचटका में 8.8 तीव्रता से आया था।

➤ अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में 31 अगस्त 2025 को 6 तीव्रता का भूकम्प आया।

वर्ष 2025 में विश्वभर में 1792 झटके भूकम्प के महसूस किये गये।

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आंकड़ा

220	40	50	50,000
अरब डॉलर का नुकसान हुआ दुनिया को	अरब डॉलर की क्षति लॉस एंजिल्स में आग से हुई	अरब डॉलर की क्षति 143 चक्रवातों के कारण हुई	लोग भूकम्प से थाइलैण्ड व म्यामांर में मारे गये

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि तबाही के अगर यदि ऐसे ही सुरसा का फैलता मुँह बने रहे, तब इसके परिणाम के रूप में (द्वितीय हरित क्रान्ति) का सपना जमींदोज हो जाएगा। 'लैसैट' की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 में 20 दिन 'घातक लू' चली और समूचे विश्व में प्रति मिनट एक व्यक्ति 'हीट स्ट्रोक' का शिकार हुआ। यही नहीं वर्ष 2022 में वायु प्रदूषण ने 17.2 लाख भारतीयों के प्राण हर लिये, जो 2010 की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक है।

भारत की गिनती संसार के उन देशों के मध्य होती है जहाँ मौसमी अति से सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित होती है। नस्लीय सोच वाले कहने के लिए स्वतंत्र हैं कि विकासशील देशों के लोग अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, लेकिन कुदरत भेदभाव नहीं करती। 'क्लाइमेट सेंट्रल ग्रुप' के अनुसार 2025 के शुरुआती छह महीनों में ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण अमेरिका को 101 बिलियन डॉलर नुकसान के साथ ही 400 लोगों की जान से भी हाथ धोना पड़ा। विकसित देश अमेरिका एवं उनके अन्य पश्चिमी देश इस मुद्दे पर संजीदगी से कोई ठोस पाय क्यों नहीं करते? यह धरित्री हम सबकी है किन्तु इसकी दुर्गति के प्रथम कुसूरवार तो वही हैं। औसत वैश्विक तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है। जलवायु संकटों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UFCCC) करता है। अब तक जलवायु नीति पर पश्चिमी देशों की सोच हावी रही है जो जलवायु को व्यापार अथवा सिर्फ एक संसाधन के रूप में मानती है। औद्योगिक क्रान्ति के कारण पश्चिमी देश आर्थिक रूप से सम्पन्न हुए किन्तु इसकी कीमत जलवायु के पैटर्न में भारी बदलाव के रूप में संपूर्ण मानव जाति चुका रही है। हद तो यह हुई कि इन देशों द्वारा कमजोर देशों की सहायता न तो वित्तीय और न तकनीकी रूप में करने का वादा पूरा किया।

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विचार-विमर्श (An Analysis on Conservation of Natural Resources)– (ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में भारत का भविष्य)

प्रकृति के संरक्षण के लिए आज पर्यावरण अनुकूल विकास को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सन् 1972 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए 5 जून को 'विश्व पर्यावरण दिवस' आयोजित करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो पर्यावरणीय समस्याओं के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है और साथ ही उसका प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन भी कम है। पश्चिमी देशों के असहयोगात्मक रवैये के बावजूद भी वह 'कॉप सम्मेलनों' में 'ग्लोब साउथ' की आवाज तर्कपूर्ण तरीके से उठाता रहा है। आज बिगड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र और जैव-विविधता को बचाने के लिए हमें अपनी परम्पराओं की ओर लौटना होगा यानि घर वापसी का समय आ गया है। परम्परागत ऊर्जा

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

संसाधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ ही इको-फ्रेंडली तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता को देखते हुए आज सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर एवं बायो गैस फ्यूल पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया एवं विकसित भारत की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है जिनका विवरण इस प्रकार है-

- पीएम सूर्यघर : मुफ्त बिजली योजना (P.M. Surya Ghar : Muft Bijli Yojna)
- राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission)
- सोलर पार्क योजना (Solar Park Scheme)
- पीएम कुसुम (PM KUSUM)
- सौर पीवी मॉड्यूल पीएलआई योजना (Solar PV Module PLI Scheme)
- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (National Bio-Energy Programme)
- पवन ऊर्जा विकास (Wind Energy Development)

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' द्वारा सम्बन्धित प्रभागों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसके अभी तक के परिणाम एवं प्रभाव उत्साहजनक नजर आ रहे हैं। भारत में बिजली की मांग 51.5 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा (जुलाई 2025) और 51 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता (सितम्बर 2025) हासिल कर ली है, जो 2030 के लक्ष्यों को पार कर गयी है।

भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भी अक्षय ऊर्जा का लाभ लेने में सक्षम है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के एवं विशाल समुद्री तट होने के कारण ज्वारीय ऊर्जा की भी असीम संभावनायें हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत न ही कभी समाप्त होने वाले हैं और न ही किसी प्रकार वातावरण को हानि पहुँचाते हैं। वर्तमान में लगभग 80 प्रतिशत ऊर्जा की आपूर्ति का स्रोत जीवाश्म ईंधन हैं। जीवाश्म ईंधन जलने पर कार्बन एवं ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 'जलवायु परिवर्तन' के गंभीर परिणामों से संपूर्ण विश्व प्रभावित हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु ऊर्जा के अन्य विकल्पों पर भी विचारपूर्वक मंथन करने की आवश्यकता है। पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु जनजागरूकता अभियानों के माध्यम से 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को आधे स्तर तक लाना होगा जिससे सभी को स्वच्छ, सस्ती विश्वसनीय एवं हटकाऊ ईंधन की प्राप्ति हो सके।

वैश्विक आबादी का 80 प्रतिशत जीवाश्म ईंधन की पूर्ति का स्रोत आयातक देशों द्वारा होती है किन्तु राजनीतिक संकट के समय इनकी स्थिति सोचनीय हो जाती है। जैसा कि विगत कुछ समय से रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान-इराक युद्ध, इजराइल-इराक युद्ध या हाल ही में (फरवरी 2026) अमेरिका एवं इराक में युद्ध होने की संभावनायें उत्पन्न हो गयी हैं, जिसका परिणाम राजनीतिक के साथ आर्थिक एवं सामाजिक खामियाजा भुगत के ही पूरा होता है।

आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा की दृष्टि से दुनिया में तृतीय सबसे बड़ा उत्पादक देश है और हमारी संस्थापित बिजली क्षमता का लगभग 42 प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। वर्ष 2023 के अनुसार भारत की अनुमानित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़े हाइड्रो के अलावा) लगभग 1.5

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

मिलियन मेगावाट ह जिसमें 50 प्रतिशत सौर ऊर्जा से, 46.7 प्रतिशत पवन ऊर्जा से और शेष हाइड्रो, बायोमॉस और कचरे के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का हिस्सा है।

गुजरात का 'सूर्याग्राम' (मोढेरा) देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है जहाँ रूफटॉप सोलर सिस्टम एवं ग्राउण्ड माउंटेड सोलर पावर प्लांट, भवनों में लगाये गये हैं। बायो विलेज में बायोगैस, बी कीपिंग, सोलर एनर्जी और बायोफर्टिलाइजर पर पूरा जोर दिया जाता है एवं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के उपायों पर फोकस किया जा रहा है।

सौर ऊर्जा (Solar Energy) : – पिछले एक दशक से सौर ऊर्जा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमों एवं विकेन्द्रीकृत और वितरित अनुप्रयोगों के उपयोग में वृद्धि देखी गयी है। सौर ऊर्जा से ग्रामीण एवं शहरी प्रत्येक क्षेत्र लाभान्वित हो रहे हैं किन्तु ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चियों के जीवन की राह भी आसान हुई है क्योंकि ईंधन इकट्ठा करने हेतु जंगलों से लकड़ियां लाना जाना जहाँ अत्यधिक श्रम का काम था वहीं चूल्हे के धुयें से फेफड़ों एवं आँखों का नुकसान कम हुआ है। 'राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान' की रिपोर्ट बताती है कि तीन प्रतिशत (3%) बंजर भूमि को सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल से कवर करने पर 748 गीगावाट बिजली उत्पन्न हो सकती है।

वर्तमान में सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग हेतु प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिसके अंतर्गत घर की छतों पर सौर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए सबसिडी दी जाती है जिसका लक्ष्य है, 2026–27 तक एक करोड़ घरों तक इसका लाभ पहुँचाना।

2 किलोवाट– 60% सब्सिडी

2–3 किलोवाट– 40% सब्सिडी

● **पी0एम0– कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान)–** यह योजना ग्रामीण इलाके के लिए एक अति लाभकारी योजना है जिसका उद्देश्य खेतों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करके सौर यंत्रों को स्थापित करना है। यह किसानों हेतु अतिरिक्त आय का साधन साबित हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत स्टैण्ड अलोन सोलर पम्पों की स्थापना और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पम्पों के सोलराइजेशन के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत तक केन्द्र सरकार सब्सिडी देती है। इस लाभ के अलावा किसान अपनी बंजरभूमि पर इस योजना के अंतर्गत 2 मेगावाट तक के ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगवा सकते हैं और राज्य नियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ पर स्थानीय डिस्कॉम को बिजली बेच सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता को जोड़ना है, जिसमें कुल केन्द्रीय वित्तीय सहायता 34,422 करोड़ है।

पी0एम0 सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना :- यह योजना दुनिया की सबसे वृहद घरेलू रूफटॉप सौर योजना (PMSG : MBY) का लक्ष्य मार्च 2027 तक 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक करोड़ सौर इंस्टालेशन को स्थापित करना है। इसकी शुरुआती फरवरी 2024 में की गयी थी और इसकी सफलता का आंकलन इसी बात से पता चलता है कि शुरुआत के नौ महीनों में 6.3 लाख इंस्टालेशन किए जा चुके थे। इस योजना के माध्यम से रूफटॉप सौर ऊर्जा में एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इस योजना ने व्यापक जागरूकता अभियान, उपभोक्ता प्रक्रियाओं का सरल होना, नियामक बाधाओं का निवारण एवं किफायती वित्तपोषण विकल्प जैसी सभी बातों के कारण अपार सफलता प्राप्त की है। यह योजना परिचालन

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

मजबूत को प्रदर्शित करती है। फरवरी 2026 तक 30 लाख से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित किये जा चुके हैं।

पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना (एक संक्षिप्त जानकारी)

- योजना का शुभारंभ 15 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है।
- केवल मार्च 2025 तक 10 लाख घरों में सोलर पैनल स्थापित हो चुके थे।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है।
- **सोलर पार्क और अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास** – उपरोक्त परियोजना को दिसम्बर 2024 में प्रारम्भ किया गया, जिसका लक्ष्य परियोजना डेवलपर्स को आसानी से सहायता प्रदान करना था। इस योजना का उद्देश्य 31 मार्च 2026 तक 40 गीगावाट की संचयी क्षमता वाले कम से कम 25 सोलर पार्कों की स्थापना करना है जिससे बिजली उत्पादन हेतु सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना में तेजी लाना भी है।
- **सौर विनिर्माण और पीएलआई योजना**– सरकार द्वारा 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम पर जोर देते हुए घरेलू सौर विनिर्माण के द्वारा सौर पारिस्थितिकी तंत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्ति का लक्ष्य तय किया है। भारत सरकार द्वारा उच्च दखता वाले सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 24000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा में आयात निर्भरता को कम करना है।
- **पवन ऊर्जा (Wind Energy)**– अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन के अनुसार, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण वृद्धि दर्ज की जा रही है। फ्लोटिंग टरबाइन प्रौद्योगिकी के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा का दोहन हो सकता है। इस प्रकार के नवाचार पवन धाराओं के द्वारा अधिक मात्रा में ऊर्जा के दोहन को आसान बनाते हैं एवं विकास के नवीन क्षेत्रों को भी खेलते हैं। विंडफ्लोट समुद्र तल पर किसी भी निर्माण के बिना टरबाइन का समर्थन करता है। विंडफ्लोट पवन ऊर्जा प्राप्त करने की उच्च क्षमता की प्रवृत्ति पतंग पवन ऊर्जा प्रणालियां उच्च ऊँई वाली हवाओं को पकड़ने के लिए जमीन से बंधी बड़ी पतंगों का उपयोग करती हैं। ऊर्जा पतंगों द्वारा पारम्परिक पवन टरबाइनों की तुलना में अधिक व स्वच्छ ऊर्जा प्रदान की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से पवन टरबाइनों के उपयोग को अधिक लाभकारी बना रहा है।
- **जलविद्युत ऊर्जा (Hydropower Energy)**– जलविद्युत नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक बड़ा स्रोत है। 2050 परिदृश्य तक शुद्ध शून्य उज्सर्जन में, जलविद्युत प्रतिवर्ष लगभग 5500 टेरावॉट घंटे (टीडब्ल्यूएच) बिजली प्रदान करने के लिए 2023–2030 में 4 प्रतिशत के लगभग औसत वार्षिक उत्पादन वृद्धि दर प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करता है। 2022 में पनबिजली उत्पादन लगभग 70 प्रतिशत टीडब्ल्यूएच (2 प्रतिशत के करीब) बढ़कर 4300 टीडब्ल्यूएच तक पहुँच गया। जलविद्युत ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा प्राप्ति हेतु उन्नत टरबाइनों का प्रयोग किया जाता है। यह पर्यावरणीय प्रभावों को बहुत कम कर देता है। ज्वारीय ऊर्जा प्रणालियों में

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

नवाचारों में पानी के नीचे टरबाइन और बैराज शामिल हैं, जो ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। गतिज हाइड्रो टरबाइन के माध्यम से बहते हुए पानी अथवा नदियों और नालों के जैसे छोटे पैमाने के जल स्रोतों का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जा सकता है।

- **परमाणु ऊर्जा (Atomic Energy)**— पर्यावरणीय दशाओं के गंभीर होते वातावरण में परमाणु ऊर्जा कम कार्बन वाली बिजली स्रोत प्राप्ति का दूसरा सर्वाधिक बड़ा स्रोत है। आईईए(IEA) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा उत्पादन को औसतन 3 प्रतिशत सालाना बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनवरी 2026 तक वैश्विक स्तर पर लगभग 404–411 सक्रिय परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी क्षमता लगभग 369–371 गीगावाट (GW) है। रूस और चीन ही दो देश हैं जहाँ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। माइक्रो रिएक्टर 1–10 मेगावाट का उत्पादन करते हैं एवं मोबाइल होते हैं जिसके कारण यह दूरदराज के क्षेत्रों हेतु उपयोगी है।

भूतापीय ऊष्मा (Geothermal Energy)— पृथ्वी एक बॉयलर के रूप में कार्य करती है जिसमें भूतापीय तरल पदार्थ 3000 मीटर की गहराई तक जलाशयों में होते हैं और ड्रिलिंग द्वारा कुओं से प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी की कोर में उपस्थित पोटेशियम, थोरियम, यूरेनियम के रेडियोधर्मी आइसोटोप द्वारा ऊष्मा प्राप्त की जाती है। भू-तापीय ताप में अगली पीढ़ी की तकनीक में 'सुपरहॉट रॉक एनर्जी' शामिल हैं जहाँ 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान को गहरी ड्रिलिंग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे सैद्धान्तिक रूप से दुनिया की बिजली आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त माना जाता है।

भारत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भी सक्रिय हैं जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों और जैव ईंधनों जैसे स्वच्छ परिवहन के समाधानों को अपना रहा है। भारत आज ग्रामीण विकास में हरित प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग कर रहा है। सतत कृषि की लक्ष्य प्राप्ति हेतु कृषि अनुसंधान और विकास ने नवीन प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के लिए प्रेरित किया है। जैविक खेती, कृषि वानिकी, एकीकृत कीट प्रबंधन, मिश्रित खेती, हरित नैनो प्रौद्योगिकी एवं स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों के साथ फसल चक्रण भी सामाजिक-आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है।

जल दुर्लभ संसाधनों में से एक है। हरित प्रौद्योगिकी द्वारा जल के पुनर्प्रयोग को संभव बनाया जा सकता है। बंगलुरु जैसे ही अन्य शहरों के जल की कमी को पूर्ण करने में पर्यावरण अनुकूल किन्तु लागत प्रभावी विकल्प तैयार करने में ग्रीन प्रौद्योगिकी समृद्धि व जीवन स्तर को प्रेरित करके आर्थिक अवसरों का भरपूर उपयोग कर सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion) :- भारत सरकार का 'विकसित भारत' का दृष्टिकोण ऊर्जा क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है। सुरक्षित जलवायु के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाना होगा एवं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु आवश्यक ठोस प्रयास की अत्यंत आवश्यकता है। भारत द्वारा पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई सराहनीय प्रयास जारी हैं जिससे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है एवं एक स्थायी एवं न्यायसंगत ऊर्जा प्रणाली में बदलाव के लिए भी हमारा देश प्रतिबद्ध है।

'पंचामृत' एक पांच सूत्री योजना है जिसका उद्देश्य 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500

Research Stream

A Bi-Annual, Open Access Peer Reviewed International Journal

Volume 03, Issue 01, March 2026

गीगावाट तक बढ़ाना एवं देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से 50 प्रतिशत तक पूरा करना है। इसके साथ ही कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करना एवं 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह मिशन एक स्वच्छ, हरित एवं भविष्य के लिए सुरक्षित जलवायु पारिस्थितिकी को बढ़ावा देता है। जलविद्युत पवन एवं सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में भारत चौथे स्थान पर है जिससे लगभग जीवाश्म ईंधन से कार्बन उत्सर्जन में 1.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी। भारत सहित दुनिया के 80 फीसदी देशों में हरित ऊर्जा को बढ़ाने की कवायद तीव्र गति से की जा रही है। इण्टरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार वर्ष 2030 तक हरित ऊर्जा की क्षमता मौजूदा समय के मुकाबले लगभग दोगुना (4600 मेगावॉट) हो जाएगी। 2025 के अंत में अमेजन के जंगल में कॉप-30 सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य दुनिया के वनों की सुरक्षा के लिए प्रेरित करना था। वैश्विक कोशिशों के कारण ही अमेजन के जंगलों में बीते 14 महीनों में पेड़ों की कटाई 11 फीसदी कम हुई है। दुनिया भर के मात्र 1 प्रतिशत महासागरीय क्षेत्र ही सुरक्षित हैं जिसको सितम्बर 2025 में 30 प्रतिशत तक करने पर वैश्विक सहमति बनी है।

भारत जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध राष्ट्र है जहाँ बीते एक दशक में बाघों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गयी है (3600)। इसके साथ ही भारत दुनिया के 75 प्रतिशत बाघों का आलय बन गया है। फ्लोरिडा में कछुओं की संख्या में सुधार हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है जो कि किसी विशेष देश से सम्बन्धित नहीं है। यह एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए क्योंकि प्रकृति है तो हमारा अस्तित्व भी है।

संदर्भ सूची—

1. कुरुक्षेत्र (जुलाई 2025)
2. कुरुक्षेत्र (मई 2024)
3. डाउन टू अर्थ
4. हिन्दुस्तान (26 दिसम्बर 2025)
5. क
6. क
7. पर्यावरण (हिन्दी पत्रिका) (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत)
8. 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 (18वीं)